



## हादसों की हद

एक बार फिर वीरवार को जम्मू-कश्मीर में प्रद्वालुओं से भरी बस खाई में गिर गई। इसमें बाईस लोगों की मौत हो गई और 57 घायल हो गए। डेढ़ सौ पूर्ण गहरी खाई में बस गिरने से राहत-बचाव कार्य में बाधा आई। इतनी गहराई में बस गिरने से यात्रियों के पीड़ियों का एक कांप उठा दिया गया। ऐसे छोटे-बड़े हादसों में निर्दोष लोगों की मौत की खबरें रोज अखबारों की सुरिखियां बनती हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बस तेज गति के चलते एक कार को बचाने के प्रयास में एक तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। कतिपय सूचना माध्यमों में चालक को नींद आने की बात भी कही गई। निस्सदैंह, ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय लापरवाही ही होती है। यह विचारणीय तथ्य है कि मैदानी इलाकों से जटिल पर्वतीय मार्गों पर बस ले जाने वाले चालकों को क्या पहाड़ी रास्तों पर बस चलाने का पर्याप्त अनुभव होता है? जो तीखे मोड़ पर बाहन को नियंत्रित कर सकें। दरअसल, जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पहाड़ी इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं में मानवीय क्षति ज्यादा होती है। वजह साफ है कि गहरी खाई बचाने के मैके कम ही देती हैं। यह बिंदंबना है कि बड़े हादसों के बाद शासन-प्रशासन की तरफ से मुआवजे व संवेदना का सिलसिला तो चलता है लेकिन हादसों के कारणों की तह तक नहीं जाया जाता। यदि हादसों के कारणों की वास्तविक वजह सार्वजनिक विमर्श में आए तो उससे सबक लेकर सैकड़े लोगों की जान बचायी जा सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ करीब साढ़े चार लाख लोग इन दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। इनमें कई लोग तो जीवन भर के लिये विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में नीति-नियंत्रणों की तरफ से बेमौत मरते लोगों का जीवन बचाने की ईमानदार पहल नहीं होती। हाल के वर्षों में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ। सड़कें चौड़ी और सुविधाजनक हुईं। लेकिन रफ्तार का बढ़ना जानलेवा साक्षित हो रहा है। कहीं-दूकहीं सड़क निर्माण तकनीकी में चूक भी हादसों की वजह बनने की खबरें आई हैं। वहाँ बड़ी संख्या में हादसों की वजह अनियंत्रित रफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन तथा शराब पीकर बाहन चलाना रहा है। यदि दुर्घटनाओं के कारणों में विस्तार से जाएं तो बाहन चलाने के अनुभव के बिना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना व ट्रक चालकों की आंखों की नियमित जांच न होना भी समें आता है। दरअसल, बाहनों की पिंचेस, सार्वजनिक बाहन चालकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच तथा निर्धारित समय तक ही बाहन चलाने की अवधि भी तय की जानी चाहिए। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि चालक की नींद पूरी न होने और उसे पर्याप्त आराम न मिलने से हादसा हुआ। चिंता की बात यह भी है कि लोग रात में सफर करना सुविधाजनक मानने लगे हैं। जबकि रात को बाहन चलाना कई मायनों में असुरक्षित होता है और किसी हादसे के बाद पर्याप्त सहायता व उपचार न मिलना जानलेवा साक्षित हो सकता है। इन दुर्घटनाओं का दुखद पहलू यह है कि मरने वाले में अधिकांश युवा व परिवार के कमाने वाले सदस्य होते हैं। हादसे के बाद पूरा परिवार गरीबी के दलदल में चला जाता है। यह राष्ट्र की बड़ी आर्थिक क्षति होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि यदि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या रोकी जा सके तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीन प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। नीति-नियंत्रणों को इस बात पर भी विचार करना होगा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में बाहन कम होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में क्यों होती हैं?

## जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को पुनः निर्धारित करने की तैयारी

५७ कद्र सरकार के साथ एक नहयून मुद्रा संकाल वर्लू उपाय (जोड़ा) और अन्य प्रमुख आर्थिक गणनाओं के उद्देश्य से आधार वर्ष को संशोधित करने की आवश्यकता है। आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष होता है जिसकी कीमतों का उपयोग, महत्वपूर्ण रूप से, वास्तविक जीडीपी विकास दर की गणना करने के लिए किया जाता है। ऐसे आधार वर्ष के निर्णय अन्य मेट्रिक्स जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए भी प्रासंगिक हैं। भारत वर्तमान में 2011-12 के आधार वर्ष का पालन करता है। जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने भारत के राष्ट्रीय खातों के लिए 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में घोषित किया। संशोधन ने 2004-05 के पिछले आधार वर्ष को बदल दिया और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप था, जिसने हर पांच साल में आधार वर्ष बदलने की बकालत की थी। आधार वर्ष चुनना और उसे संशोधित करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, व्योकि वे संरचनात्मक परिवर्तनों को ट्रैक करते हैं। एक चरम मामले के रूप में कल्पना करें कि भारत का आधार वर्ष 1980-81 (एक पुरानी श्रृंखला, जिसे बाद में 1993-94 श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) पर अपरिवर्तित रहा। इतने पुराने आधार वर्ष के साथ परिणामी जीडीपी डेटा भारत में हुए विशाल संरचनात्मक परिवर्तन को पकड़ने में असमर्थ होता, खासकर 1991 के बाद से, आईटी क्षेत्र के विकास के साथ। जीडीपी में संशोधन और आधार वर्ष को अपडेट करने से सांख्यिकीविदों को आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्व को फिर से तौलने की अनुमति मिलती है। यह विधियों और डेटा स्रोतों में आगे के बदलाव या पुनर्विचार की भी अनुमति देता है। आधार वर्ष संशोधन राष्ट्रीय खातों में वार्षिक संशोधनों से बहुत अलग हैं। एक वार्षिक संशोधन केवल उपलब्ध डेटा में परिवर्तन को शामिल करता है और ऐसे डेटा को अपडेट करता है, लेकिन बुनियादी वैचारिक ढाँचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। वर्षों में सख्त तुलना सुनिश्चित करने के लिए, यह किसी भी नए और बेहतर डेटा स्रोतों का उपयोग नहीं करता है। दूसरी ओर, आधार वर्ष संशोधन न केवल संदर्भ वर्षों को बदलते हैं, बल्कि अद्यतन सर्वेक्षणों और अध्ययनों का उपयोग करते हैं, और वैचारिक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। भारत, 1948-49 से, हर 10 साल में एक बार आधार वर्ष में संशोधन करता आ रहा था। इतना लंबा अंतराल उचित था क्योंकि अगले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत कम बदलाव हुए। आर्थिक मेट्रिक्स के लिए आधार वर्ष को उस वर्ष के साथ सरीखित किया गया था जिसमें जनसंख्या जनगणना की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्यबल के बारे में जानकारी आधार वर्ष के अनुमानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और कार्यबल के अनुमान दशकों जनगणना से प्राप्त किए जाते थे। हालांकि, फरवरी 1999 में CSO ने इस प्रथा से किनारा कर लिया और 1980-81 की श्रृंखला को 1990-91 की श्रृंखला के बजाय 1993-94 की श्रृंखला से बदल दिया।

# संविधान की रक्षा लोकसभा चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा

पी. सुधीर

---

इसमें काइं सदह नहीं है कि भारत का सर्विधान और इसकी सुरक्षा लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दों में से एक रहा। शुरू से ही, इंडिया गवर्नेंस की घटक पार्टियों के नेताओं ने अपने चुनावी मंच पर सर्विधान की रक्षा को केंद्रीय विषय के रूप में पेश किया था। इसका लोगों की एक बड़ी संख्या पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने पिछले एक दशक में देश में सत्तावादी शासन के विभिन्न पहलुओं का कटु अनुभव किया था। विपक्ष का सर्विधान खतरे में विषय मोदी के भाजपा के लिए 400 से अधिक सीटों के आह्वान के साथ मेल खाता था। सर्विधान बदलने की धमकी को भाजपा के विभिन्न नेताओं द्वारा यह तर्क दिये जाने से बल मिला कि सर्विधान बदलने के लिए 400 सीटें या बड़ा बहुमत चाहिए। 9 मार्च को ही भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि- भाजपा लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य इसलिए रख रही है, क्योंकि सर्विधान बदलने के लिए संसद में उसे दो- तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। फैजाबाद से भाजपा सांसद लल्लू सिंह, नागौर से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा और मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये। विपक्ष के इस अभियान को कि यह चुनाव सर्विधान की रक्षा के लिए है, भाजपा उम्मीदवारों के ऐसे बयानों से और मजबूती मिली। भाजपा नेताओं, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जल्द ही इस बारे में रिपोर्ट मिल गई कि सर्विधान को खतरा का संदेश जनता

The image shows the Constitution of India, a thick black book with gold-colored lettering on the cover. The title "CONSTITUTION OF INDIA" is written in large, bold, capital letters at the top. Below the title is the Indian state emblem, which depicts a Lion Capital of Ashoka. The book is set against a background of a yellow and white geometric patterned fabric.

तक पहुंचाने वाले लागा की सख्त्या बढ़ रही है, खासकर दलितों के बीच, जो समिधान के निर्माता डॉ. अंबेडकर का बहुत ही सम्मान करते हैं। यही कारण है कि मोदी ने विपक्ष के आरोपों का आक्रामक तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। मतदान के पहले चरण से पहले ही मोदी ने घोषणा कर दी थी कि पार्टी के लिए समिधान परिव्रत पुस्तक है, सरकार के लिए समिधान गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल और कुरान है, और यहां तक कह दिया कि शबाबासहेब अंबेडकर भी इसे नहीं बदल सकते। यह तीखी आवाज और जवाबी हमला कि कग्रेस और इंडिया ब्लॉक हो समिधान को बदलेग, सरासर झूठा आरोप था। वास्तव में इंडिया ब्लॉक का आरोप भाजपा नेताओं को चुभ गया और इसलिए अपराधबोध वाली ऐसी तीखी प्रतिक्रिया हुई। समिधान खतरे में का दूसरा पहलू जिसने मोदी को परेशान किया, वह यह आरोप था कि समिधान में बदलाव से एससी, एसटी और ओवेसी के लिए आरक्षण खत्म हो जायेगा। मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं के एक समूह ने इस डर को व्यक्त किया। मोदी ने समिधान बदलने के मुद्दे को सांप्रदायिक मोड़ देकर जवाबी हमला करने की कोशिश की। एक

बाद एक भाषणों में मोदी ने घोषणा की थी कि इंडिया ब्लॉक संविधान बदलना चाहता है, ताकि एससी, एसटी और ओबीसी के नए आरक्षण काटकर मुसलमानों को धर्म विश्वास दें। आधार पर आरक्षण दिया जा सके। मोदी और अमित शाह दोनों ने कर्नाटक और गुजरात लंगाना में ओबीसी श्रेणी के तहत मुसलमानों को दिये गये 4 प्रतिशत आरक्षण दिया हवाला दिया। लगातार यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक न केवल आरक्षण छीन लेंगे, बल्कि हिंदुओं की अपनी भी मुसलमानों को सौंप देंगे। लेकिन उछड़े घोषित किये गये और ओबीसी दर्जा माहौल है। मोदी शासन के दस वर्षों ने राज्य के सभी संवैधानिक निकायों और संस्थाओं को नष्ट कर दिया है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जिस तरह से खुदको संचालित किया है, उससे यह आशंका पैदा हुई है कि क्या वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी कर सकता है? प्रधानमंत्री की भड़काऊ सांप्रदायिक चुनाव प्रचार को रोकने में घोर विफलतात्य व्यापक मतदान के आंकड़े उपलब्ध कराने में दिखाई गई अनिच्छा और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही ऐसा करना और दिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मोदी ने यह अजीबोरीब दावा किया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह परमात्मा ही है जिन्होने उन्हें देश और लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी और के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के प्रति हैं। अब जबकि उन्होंने मतदान के अंतिम चरण के दौरान कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला पर 48 घंटे ध्यान में बिताने का फैसला किया है तो यह देखना बाकी है कि उनके भविष्य के कार्य संवैधानिक रूप से अनिवार्य होंगे या ईश्वर द्वारा निर्धारित।

# एकाधिक प्रैक्टर

यह रहा जाएं को जिन्हें क्यों ठीक



नियत्रण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इस मामले में भारत उस देश से कितना अलग है, जिसकी राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई है, यानी ग्रेट ब्रिटेन। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के इदं-गिर्द व्यक्तित्व का कोई पंथ नहीं है। मुख्य विषयकी दल के नेता, लेबर के कोर स्टारमर, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। दोनों ही कड़ी मेहनत और पार्टी के सहयोगियों को अपना समर्थन देने के लिए राजी करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं।

एक बार जब वे अपने सहयोगियों का विश्वास या सम्मान खो देते हैं, तो वे चुपचाप पट छोड़ देते हैं, और उनकी जगह ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो खुद के दम पर बने हैं, न कि राजनीतिक वंशवादी, और इन्हें घमंडी नहीं कि वे यह मान लें कि वे पूरे देश की बात कर रहे हैं। भारत में पार्टी प्रणाली भ्रष्ट और जीर्ण-शीर्ण है। इस बीच, भारतीय राज्य मनमाना और मनमानी कर रहा है। सिविल सेवाओं और पुलिस को सविधान के प्रति अपनी निष्ठा के कारण स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। वास्तव में, वे अपने राजनीतिक आकाओं की मांगों का जवाब देते हुए अत्यधिक समझौतावादी हो गए हैं। यह केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी सच है, जहाँ IAS या IPS अधिकारी के लिए, पदोन्ति और वरीयता अक्सर पेशेवर उत्कृष्टता की तुलना में मरियों के साथ निकटता पर अधिक निर्भर करती है। इस बीच, चुनाव

याग जसा नियमिक संस्थाओं का भा  
यीर्षस रूप से स्वतंत्र नहीं माना जाता है  
और वे सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आने  
लिए बहुत अधिक प्रवण हैं। भारत की  
कोकतांत्रिक साख ऐसे कानूनों के अस्तित्व  
और भी अधिक खराब हो गई है, जिनके  
हत नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के  
लल में डाला जा सकता है और उन्हें कई  
रोषों तक जेल में रखा जा सकता है। इन  
कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों,  
सास्तव में, किसी भी तरह के असहमति  
जानने वालों को डारने और चुप कराने के  
लए किया गया है। कानून के इस दुरुपयोग  
अदालतें भी शामिल रही हैं। न्यायाधीश  
में बहुत ही सुस्त रहे हैं और आश्रयनक  
ने यूपीए जैसे कानूनों को कानून की  
हने दिया है, जिसका सभ्य समाज में कोई  
होना चाहिए। संक्षेप में, ये हमारी  
कमियाँ हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े  
ने के आडंबरपूर्ण दावों के पीछे छिपी हैं,  
बुद्ध लोकतंत्र की जननी होने के। दूसरा  
या की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी  
होने का दावा भी कई पापों को छुपाता  
आर्थिक उदारीकरण ने वास्तव में गरीबी  
दी है, इसने असमानता को भी बढ़े पैमाने  
माना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि  
थ नौकरियों में भी वृद्धि नहीं देखी गई  
भारत अरबपतियों के उत्पादन में विश्व में  
शक्ति युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत  
और महिलाओं के बीच कार्यबल में  
दर बेहद कम है। भारत का आर्थिक  
जुला है; और इसका पर्यावरण रिकॉर्ड  
है। भारत के आर्थिक उछल के शोपीस  
में जल संकट और भारत के वैश्विक  
पोर्पीस शहर New Delhi में यायु प्रदूषण  
र, दोनों ही इस बात की अभिव्यक्ति हैं  
अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली  
वास्तविकताओं की कितनी बेरहमी से  
की है।

आज का राशी फल					
मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या
तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन

**हुए वर्तमान का**  
लाने में आपका  
को लेकर पूरे  
पड़ेगा।

**प्रियजनों का**  
सार्थक होने का  
द होगा। शिक्षा-  
होगा।

**इन्हीं योजनाओं**  
**विवरण-** परिवार में  
यण संबंधों को  
कार की शंका न  
सगे- संबंधों में  
भच्छे कार्यों द्वारा  
प्रगाढ़ता बढ़ेगी।  
वसर प्राप्त होगे।  
विनि हेतु प्रयत्नशील  
यान रखें।  
प्रभावित होगा।  
साथ समझौता  
नहीं। जीवनसाथी

**से व्याराक मतभेद संभव।**

**तुला:-** आज सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

**वृश्चिक:-** आज परिजनों के सुख-दुख से प्रभावित मन परिवार को एकजुट रखने में केंद्रित होगा।

**धनु:-** निराशावादी विचारों को त्याग आशावादी बनें। नाजुक संबंधों के बीच भावनात्मक कथ्यों को भूल वर्तमान को बेहतर बनायें। परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा।

**मकर:-** मन सुंदर विचारों से सिंचित होगा। धार्मिक व पारंपरिक कायरें की ओर मन केंद्रित होगा। नये कायरों में संलग्नता से लाभ संभव। आलस्य का त्याग करें।

**कुभि:-** अपने सुख-दुख को छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। नयी आकांक्षाएं मन को उद्विलित करेंगी। पुराने संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

**मीन:-** किसी अचल सम्पति को लेने की योजना बन सकती है। कार्यक्षेत्र के किसी सहकर्मी से मतभेद संभव। धनागम की नयी युकियों पर मन केंद्रित होगा। जीवन साथी का भावनात्मक स्नेह प्राप्त होगा।

# तेलुगुभाषी दो राज्यों में कही है चुनावी टक्करा

गठबंधन का दिखावा करते हुए भी तेलंगाना के गठन के बाद 2014 में हुए चुनावों में कांग्रेस को धोखा दिया। केसीआर ने जनता को यह दिखाने के लिए सफलतापूर्वक लॉबिंग की थी कि वे तेलंगाना के एकमात्र निर्मांता थे और क्योंकि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, आमरण अनशन भी किया था इसलिए वे इसका श्रेय लेने के हकदार थे। इसी भावना का पफयदा उत्तरे हुए केसीआर ने विधान सभा की कुल 119 सीटों में से 63 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 2019 में केसीआर ने फिर से विजय प्राप्त की थी। सत्ता में आने के बाद केसीआर ने तेलंगाना सरकार को अपनी निजी जागीर बना लिया और बेटे केटी रामाराव और भतीजे हरीश राव को महत्वपूर्ण मंत्री बनाया। उनकी बेटी के कविता सांसद बनी। कई मंत्री और महत्वपूर्ण नेता उनकी ही बेलमा जाति से थे। बेलमा एक समृद्ध जाति है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहां तक कि उन्होंने बेलमा जाति के व्यवसायियों को भी बढ़ावा दिया। तेलंगाना के लिए उनकी लड़ाई में समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने केसीआर का समर्थन किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ने खुद को इन वर्गों से काट लिया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस बजह से उन्होंने अपना आधार खो दिया है। पहले हैदराबाद निजाम द्वारा शासित एक सामर्ती गैर लोकतांत्रिक राज्य था जिसके एक हिस्से पर तेलंगाना राज्य ने कब्जा कर लिया था। स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक राज्य था लेकिन लोगों की प्रकृति और नैतिकता नहीं बदली थी। ऐसा लगता है कि केसीआर की सोच थी कि वे एक राजकुमार की तरह व्यवहार करके लोगों से दूर रहकर राज्य पर प्रभावी ढंग से शासन कर सकते हैं लेकिन नए राज्य को संसाधनों की

आवश्यकता थी। तेलंगाना को यह कैसे मिलेगा? उनके बेटे केंटी रामारवाह हैदराबाद के व्यावसायिकरण की योजना के साथ आए। उहोंने यह बात तब कही थी जब 2014 में उनसे पूछ गया था कि नवाचित राज्य के लिए वे संसाधन कैसे जुटाएंगे। उहोंने कहा था - शहर हैदराबाद का इतना विस्तार करेंगे कि यह एक तरह से पूरे राज्य को कवर करेगा। इस विस्तार योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की थी जिहोंने हाईटक सिटी और विश्वस्तरीय हवाई अड्डे का निर्माण तथा शिक्षा व आईटी क्षेत्र में नए निवेश की योजना बनाई। केसीआर शासन अचल संपत्ति, इमारतों और एक वित्तीय जिले की आर्कषक योजनाओं के साथ आगे बढ़ा। इस सब के कारण जमीनों की कीमतें बढ़ गईं और बैंगलूरु व मुंबई सहित अन्य स्थानों से नए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। शहर के बड़े हिस्सों को कवर करने के लिए एल एंड टी ड्राइ एक नई मेट्रो रेल भी शुरू की गई थी। अन्य मेट्रो शहरों से आने वाले नागरिक इस चमक-धमक से अत्यधिक प्रभावित हुए। इस सब ने सरकार के राजस्व में बढ़दी की ओर अधिक सड़कों, बांधों और सिंचाई कार्यों को बनाने में खर्च किया गया। फिर भी टेकेदरों के कामों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सरकार विफल रही। नीतीजतन, जर्जर सड़कों और सिंचाई व्यवस्था के कारण जनता में नागरिगी मालूम होती है जो चुनाव परिणामों में दिखाई दे सकती है। अंध्रप्रदेश शुरू से ही काग्रेस का गढ़ रहा है। यहां तक कि आपातकाल के ठीक बाद उत्तर भारत से बेदखल होने के बावजूद पार्टी ने अंध्र प्रदेश में अपनी स्थिति बनाए रखी। विभाजन ने अंध्र में काग्रेस को घस्त कर दिया। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और तकलीन कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। संयुक्त अंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए। नए अंध्रप्रदेश की कोई राजधानी नहीं थी और लोग हैदराबाद स्थानांतरित हो गए थे। अब नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए एक ग्रीन फैल डेक्स क्षेत्र अमरावती पर ध्यान केंद्रित किया। कृष्णा नदी के तट पर अमरावती में उपजाऊ भूमि है। नायडू तमाम विरोधों के बावजूद इसे ही राजधानी बनाने पर अड़े थे। यह क्षेत्र अपीर कम्पा (नायडू की जाति) के नियंत्रण में था जो अमेरिका स्थानांतरित हो गए थे। नई राजधानी स्थापित करने के पीछे नायडू का उद्देश्य सिंगापुर और जापान से निवेश आकर्षित करने का था। नायडू ने तर्क दिया कि अमरावती एक पारंपरिक बौद्ध केंद्र था इसलिए जापान, थाईलैंड जैसे देश आकर्षित होंगे। जगन रेड़ी ने हमेशा इसका विरोध किया है। उनका मानना था कि कम्पा व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ने के लिए अमरावती को चुना गया था। कम्पा रेड़ी बंधुओं की प्रतिष्ठित जाति है और दोनों समूह एक-दूसरे के घोर विरोधी हैं। उद्घेष्यनीय है कि आंध्रप्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वार्षिक राजशेखर रेड़ी के बेटे जगन रेड़ी अपने पिता के निधन के बाद काग्रेस से अलग हो गए थे। 2019 के चुनावों में जगन रेड़ी ने जीत हासिल की। उनकी पार्टी वाईस्सआर काग्रेस ने 175 सीटों में से 151 सीटों पर कब्जा कर लिया। जगन रेड़ी ने राजधानी को कहीं अधिक विकसित शहर विशाखापत्नम में स्थानांतरित करने की योजना बनाई और इसे अपने नए मुख्यालय के रूप में घोषित किया। लेकिन अमरावती में विधानसभा और उच्च न्यायालय की इमारतें तैयार होने के कारण यह कदम आशिक ही हो सकता है। अंध्रप्रदेश विचित्र स्थिति में पंस गया है। लोगों को आशा है कि परिणाम घोषित होने के बाद राजधानी को अंतिम रूप देकर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। जगन रेड़ी को उम्मीद है कि लोगों का मुक्त या सस्ता अनुदान देने की उनकी नीति भी उन्हें चुनावों में स्थिर करने में मदत करेगी। दिक्षिण भारत में पैठ जमाने की कोशिश कर रही भाजपा ने हाल ही में वाईस्सआरसीपी के साथ अपने पहले के अलिखित गठबंधन को तोड़ते हुए टीडीपी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। पिनिशंग लाइन तक पहुंचने की होड़ में तेलंगाना और अंध्र में भाजपा की उम्मीदें अधिक बढ़ गयी हैं। वाईस्सआरसीपी अपनी जगह बनाए रखना चाहती है वहीं तेलंगाना में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाली काग्रेस सत्ता में अधिक हिस्सेदारी चाहती है जबकि भाजपा उनके किले में सेंध लगाने की पिंक में है।



